SECRETARY-GENERAL: Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on the 12th December, 2023, passed —

(i) The Appropriation (No.3) Bill, 2023; and

(ii) The Appropriation (No.4) Bill, 2023.

The Speaker has certified that these Bills are Money Bills within the meaning of Article 110 of the Constitution.

I lay a copy each of the said Bills on the Table.

GOVERNMENT BILL - *Contd.*

The Chief Election Commissioner and other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Bill, 2023

&

Amendments for reference of the Bill to a Select Committee of the Rajya Sabha

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUSHIL KUMAR GUPTA): Dr. Dinesh Sharma. You have two minutes. ...*(Interruptions)*...

डा. दिनेश शर्मा (उत्तर प्रदेश): मान्यवर, मैं सम्मानित कानून मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि ये एक पारदर्शी, निष्पक्ष और संविधान के संरक्षण में लोकतांत्रिक परंपराओं को अक्षुण्ण रखने के लिए यह बिल लाये हैं। मैं समझता हूं कि इसने सभी पक्षों को छुआ है। पहले का जो बिल था, उसके बारे में इन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया। उसमें अनुच्छेद 324 के अधीन एक अस्थायी चयन समिति का गठन किया गया था। उक्त अस्थायी समिति माननीय प्रधान मंत्री, नेता प्रतिपक्ष और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से मिलकर बनती है और इस संबंध में विधि बनाए जाने तक माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया यह अस्थायी प्रबंध है। मैं समझता हूँ कि लोकतांत्रिक परंपराओं को अनुरक्षित करते हुए अब एक स्थायी प्रबंध दिए जाने का दायित्व सर्वोच्च संस्था द्वारा निभाया जा रहा है।

मुझे उन लोगों पर आश्चर्य होता है, जिन लोगों ने संवैधानिक संस्थाओं का कभी भी पूर्णत: सम्मान नहीं किया। इमरजेंसी जैसी स्थितियां आईं, शाह बानो के प्रकरण में विभिन्न प्रकार के जो न्यायालय के निर्णय थे, उनको बदला गया, लेकिन आज जब दिए गए तथ्यों के आधार पर, पारदर्शिता के साथ, तमाम संशोधनों के साथ एक पूर्ण व्यवस्था को देने का काम इस विधेयक में किया गया है, तब इन्होंने इसके बारे में तमाम आपत्तियाँ उठाईं। मुझे इस बात को जानकर आश्चर्य होता है और विपक्ष, खास तौर से सामने बैठे हुए ऐसे लोग, जो काफी समय तक सत्ता में रहे, उनके डर को मैं नहीं समझ पाया। जब नेता प्रतिपक्ष चयन समिति में रहेंगे, तब उनको किस बात का डर है? उनके रहते हुए गलत कैसे हो जाएगा? क्या वे अपने नेता को प्रतिपक्ष के नेता के रूप

में कमजोर मानते हैं या वे यह मानते हैं कि अगली बार हमारा नेता, प्रतिपक्ष नहीं हो सकता? ...(**समय की घंटी**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUSHIL KUMAR GUPTA): Hon. Member, please conclude.

डा. दिनेश शर्मा: मान्यवर, मुझे पार्टी की तरफ से पाँच मिनट का समय दिया गया था।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुशील कुमार गुप्ता): साढ़े पाँच बजे मंत्री जी को बोलना है।

डा. दिनेश शर्मा: मान्यवर, मैं यह कह सकता हूँ कि आज इस विधेयक को लोकतांत्रिक परंपराओं की निष्पक्ष प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए और तमाम प्रकार के प्रावधानों को समाहित करते हुए लाया गया है। जो लोग यह समझते हैं कि यह सार्वभौमिक नहीं है, जो यह समझते हैं कि इसमें पक्षपात हो सकता है, तो मैं समझता हूँ कि भ्रम की स्थिति है। ...(**समय की घंटी**)... कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि जो लोग आपस में बेमेल गठबंधन में रहे, उनका भी यह कहना है कि अगर आज जेपी होते -- निश्चित रूप से अगर आज जेपी होते, तो कांग्रेस की जो मनोवृत्तियाँ थीं, जो संविधान के विरुद्ध इमरजेंसी लगाने के समय दिखीं, वे उसका विरोध करते। मैं यह मानता हूँ कि आज का यह विधेयक पूर्णत: न्यायसंगत और लोकतांत्रिक परंपराओं का अनुरक्षण करने वाला है और मैं इसका पूर्णत: समर्थन करता हूँ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUSHIL KUMAR GUPTA): Shri Binoy Viswam.

SHRI BINOY VISWAM (Kerala): How many minutes do I have, Sir?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUSHIL KUMAR GUPTA): Two minutes.

SHRI BINOY VISWAM: Sir, the total time allocated for this Bill was six hours. According to that, we have a right to get six minutes. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUSHIL KUMAR GUPTA): But here two minutes have been mentioned. ...*(Interruptions)*...

SHRI BINOY VISWAM: Sir, please tell me the reason. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUSHIL KUMAR GUPTA): Please speak. Your time has already started. ...*(Interruptions)*...

SHRI BINOY VISWAM: How can I put up my points on such an important Bill in two minutes? ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUSHIL KUMAR GUPTA): Everyone has been given two minutes. ...*(Interruptions)*...

SHRI BINOY VISWAM: No, Sir. Total time allocated for this Bill was six hours. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUSHIL KUMAR GUPTA): Your time is running out. Please start. ...*(Interruptions)*...

SHRI BINOY VISWAM (Kerala.): Sir, my time starts from now onwards for five minutes.

Sir, yesterday, this House saw a scene -- our friends from the BJP, all of them, were very vocal in supporting the Supreme Court. In a high esteem, they praised the Supreme Court yesterday. And, today, what do you see? After 24 hours, they say that Supreme Court is nothing! They forgot their words of yesterday. This is the BJP, Sir. Dr. Ambedkar was quoted here very much. Our friend, Shri Tiruchi Siva, quoted him and we all remember those words. That debate in the Assembly was meant for framing of the Constitution and was very clear. The categorical point is that the Election Commission should be free from the Executive interference and control. But they want to bring it under the control of the Executive, the Prime Minister. For them, Dr. Ambedkar is only for certain hours, certain needs. Normally, they are following the footsteps of Hitler. Hitler had a total disregard for Parliament. In 1930s, Hitler even banned the Reichstag, the German Parliament. These people are trying to sabotage the Parliamentary democracy. Free and fair elections are not important for them. That is why they want...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUSHIL KUMAR GUPTA): Please conclude. ..*(Interruptions)*...

SHRI BINOY VISWAM: The Election Commission made by the bureaucrats, controlled by the Prime Minister, obeying the diktats of the Prime Minister is going to see 'one nation, one election' theory of the BJP; it is going to make big damage to the country. And, they want to make sure that only one party would do everything here. Sir, in 2018, Shri Amit Shah made a statement for the workers of the BJP.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUSHIL KUMAR GUPTA): Please conclude

SHRI BINOY VISWAM: Sir, the last sentence. Shri Amit Shah said, if he wins the election in 2019, then, for the next 50 years, they will control India. For that purpose, they have brought this Bill. They want to make the Election Commission a goat in their farm house.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUSHIL KUMAR GUPTA): Thank you.

SHRI BINOY VISWAM: In that way, (*Time-bell rings.*) we object to it, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUSHIL KUMAR GUPTA): Shrimati Mahua Maji.

श्रीमती महुआ माजी (झारखंड): महोदय, इस बिल के पारित होते ही जो सबसे बड़ा धक्का हमारे देश को लगेगा, वह यह है कि विश्व दरबार में 140 करोड़ जनसंख्या वाले भारत को सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में और सबसे बड़ी निष्पक्ष और तटस्थ चुनावी प्रक्रिया के लिए सम्मान की नज़र से देखा जाता था, उस देश के लोकतंत्र की शुचिता संदेह के घेरे में आ जाएगी। मैं अपनी पार्टी की तरफ से इस बिल का पुरज़ोर विरोध करती हूं। यह अनैतिक है, असंवैधानिक है, बाबा साहेब अम्बेडकर तथा संविधान सभा के सदस्यों की उपेक्षा है, अवहेलना है और असम्मान है।

महोदय, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव आवश्यक होता है, जो इस बिल के पारित होते ही असंभव हो जाएगा। यदि Chief Election Commissioner की नियुक्ति में सत्तापक्ष बहुमत में होगा, तो वह चुनाव आयोग को ज़रिये निष्पक्षता और पारदर्शिता से चुनाव कैसे कराएगा? जनता कैसे यकीन करेगी कि ईवीएम और वीवीपैट में गड़बड़ी नहीं हो रही है।

महोदय, आधुनिक दुनिया के एक बहुत बड़े चिंतक फ्रांस के फूकों और इटली के अगम्बेन ने भी कहा था कि जनतंत्र की खिड़कियां खुली रहनी चाहिए, ताकि ताज़ी जनतांत्रिक हवाएं अंदर आ सकें, इससे देश मज़बूत होता है, मगर लगता है कि आजकल मुसोलिनी और हिटलर ज्यादा पढ़े जा रहे हैं।

महोदय, अभी जो चुनाव आयोग है, वह देश का चुनाव आयोग है, जैसे सुप्रीम कोर्ट देश का सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन जो बिल है, वह चुनाव आयोग को भारत सरकार का चुनाव आयोग बनाना चाहता है। अगर आप चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के पैनल से मुख्य न्यायाधीश को हटा देंगे और उस कमिटी के अध्यक्ष प्रधान मंत्री द्वारा चुने गए कैबिनेट मंत्री को शामिल करना चाहते हैं, तो आयोग वही करेगा, जो सरकार चाहेगी। आखिर सरकार Chief Justice of India को इस कमिटी से बाहर क्यों करना चाहती है? बिल के अनुसार सरकार उनकी सैलरी भी इस तरह तय करना चाहती है कि वह सरकारी आदमी लगे, अभी उसे सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर सैलरी मिलती है, जबकि सरकार नए बिल में उसे मुख्य सचिव के बराबर रखना चाहती है। लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमज़ोर करने और एजेंसियों के दुरुपयोग का इन दिनों सरकार पर लगातार इल्ज़ाम लग रहा है, तो क्या वह चुनाव आयोग को भी अपने नियंत्रण में लेना चाहती है! आखिर इस बिल की

ज़रूरत क्या है? चुनाव आयुक्त के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को क्यों नहीं होना चाहिए और इस कमिटी में, जो तीन सदस्यीय कमिटी है, उसमें अगर वोट होगा, तो वोट तो उनके पक्ष में ही होगा, तो फिर नेता प्रतिपक्ष की क्या ज़रूरत है? सरकार को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया में कोई ऐसा साम्राज्य नहीं है या कोई ऐसा राजा नहीं है ,जिसने अनंत काल तक शासन किया है। सत्ता परिवर्तन यूनिवर्सल ट्रुथ है। यदि हमारे साथियों के पास इसका कोई दृष्टांत है, तो बताएं। ...(**समय की घंटी**)... महोदय, मैं सत्ता पक्ष से आपके माध्यम से यही कहना चाहती हूं कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह तख्तो-ताज का दौर नहीं, यह राजाओं का दौर नहीं...(**समय की घंटी**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUSHIL KUMAR GUPTA): Thank you. Thank you very much.

श्रीमती महुआ माजी: यह जनशक्ति का दौर है...(**समय की घंटी**)... यह जनमत का दौर है। सब कुछ सह लेगा, हमारा यह प्यारा सा देश, मगर लोकतंत्र पर प्रहार नहीं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUSHIL KUMAR GUPTA): Ms. Indu Bala Goswami; not present. Shri Abdul Wahab; not present. Shri Neeraj Shekhar; not present. Shri Ajit Kumar Bhuyan; two minutes.

SHRI AJIT KUMAR BHUYAN (Assam): Sir, democracy and fundamental rights are the soul of the Indian Constitution, and the Election Commission has been a very strong instrument to utilize the confidence among people that their democratic rights will be safe by getting elected representatives in a free and fair election process.

Sir, there has been an amendment in the process and the manner of appointment of the Election Commission way back in 1991 when one-member Commission was converted into three-members Commission to avoid monopoly of one individual, and that amendment was supported by all political parties, including the BJP. But now the amendment that has been put for consideration in the Parliament has no consensus component and rather a bulldozing act.

Sir, the Election Commission must be perceived and honoured as independent; then democracy will flourish. I am sorry to say, the selection of an Election Commissioner will be compromised if the Government of the day has a majority monopoly. The removal of the Chief Justice of India from the selection process will certainly create a strong doubt in the minds of the people of opposition that the incumbent Government has malice intent.

Sir, my sincere suggestion will be, if the Government of the day seems to be seen as judicious in amendment of ECI Act, the Prime Minister and leader of two

major opposition parties should be made members of the selection process. Two members from the Government and a third member from the opposition cannot be a fair and unbiased selection committee of the ECI-appointment process. In the wisdom of even a layman, the proposed Bill is nothing but a majority bullet to the soul of the Constitution.

However, the Bill that has been put for consideration is not going to create confidence when already several political parties and individual constitutional experts have expressed doubt about the partiality of the ECI.

Why not two major opposition party leaders in Lok Sabha and the Prime Minister constitute a panel of the selection process to appoint the Election Commission of India?

Sir, I will conclude,

"करो सब कुछ लेकिन ऐसे न करो कि लोगों का विश्वास ही टूट जाए लोकतंत्र से,
लोकतंत्र रहेगा, तो आओगे-जाओगे, लेकिन अगर नहीं रहेगा लोकतंत्र,
तो कैसे फिर आओगे?

Thank you.

उपसभाध्यक्ष (श्री सुशील कुमार गुप्ता): सुश्री कविता पाटीदार। आपके पास दो मिनट का समय है।

सुश्री कविता पाटीदार (मध्य प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, इतने महत्वपूर्ण बिल पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद प्रेषित करती हूं। मैं अपनी बात की शुरुआत करने से पहले बताना चाहती हूं कि अभी एक माननीय सदस्य ने बात कही थी कि कोई भी राजा ऐसा नहीं रहा कि जो अनंत काल तक रहा है। मैं उसका जवाब देना चाहती हूं। राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित, बिना किसी भेदभाव के राष्ट्र हित में निर्णय लेने वाले लोगों को इस देश की जनता सिर माथे पर बैठाकर चलती है और अभी जो तीन राज्यों के परिणाम आए, वह इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है।

माननीय सभापति महोदय, भारत का चुनाव आयोग भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र को रीढ़ प्रदान करता है। यह चुनावी अखंडता का संरक्षक है। यह विधेयक मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, योग्यता, कार्यकाल और निष्कासन के प्रावधानों को एकरूपता प्रदान करता है।

(MR. CHAIRMAN *in the Chair*.)

महोदय, मैं अभी दो बिंदुओं पर बोलना चाहूंगी। विपक्ष के कुछ सदस्यों ने यह कहा है कि यह बिल सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ है। मैं उनको यह बताना चाहूंगी कि यह विधेयक

चुनाव आयोग की नियुक्ति के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप ही लाया गया है। न्यायालय ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति के माध्यम से तब तक करने का प्रावधान किया था, जब तक कि संसद एक कानून पास नहीं कर देती। वर्तमान विधेयक केवल न्यायालय द्वारा फैसले में दिए गए निर्देशों को पूरा करता है, क्योंकि अंतिम कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है और चूंकि न्यायालय ने एक तदर्थ समिति बनाई थी न कि स्थाई। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि यह मापदंड तब तक प्रभावी रहेगा, जब तक कि संसद इस मामले पर कानून नहीं बना देती। यह कानून बनाने की प्रक्रिया आज इस संसद में शुरू हो गई है।

महोदय, इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न पहलुओं को सम्बोधित करना है, इस विधेयक में अभिव्यक्तियों की परिभाषा, नियुक्ति की प्रक्रिया, योग्यताएं, खोज और चयन समिति की स्थापना, कार्यकाल की अवधि, वेतन, इस्तीफा, निष्कासन, पेंशन आदि शामिल हैं। ...(**समय की घंटी**) ...

महोदय, मैं एक और प्वाइंट आपकी अनुमति से बोलना चाहूंगी, जो कि बहुत जरूरी है। वास्तव में इस विधेयक के साथ चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में विपक्ष के नेता की भूमिका भी होती है।

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

सुश्री कविता पाटीदार: मैं आपके माध्यम से इस सदन में विपक्ष के लोगों से पूछना चाहती हूं ...

MR. CHAIRMAN: Thank you, Ms. Kavita Patidar. Dr. M. Thambidurai; two minutes.

DR. M. THAMBIDURAI (Tamil Nadu): Mr. Chairman, Sir, I was the Minister of Law, Justice and Company Affairs during 1998-99. We have seen many Law Ministers. Why the Bill could not have come in the last 71 years, I fail to understand. Now, because of the Supreme Court's intervention recently the Bill has come. I don't understand what the necessity is. That is the first part. Secondly, in the past 71 years, the Election Commission has conducted elections fairly. Otherwise, we would not have come here. Therefore, we cannot blame the Election Commission and bring such a Bill. Also, some Members from that side talked about dynastic politics. As far as the AIADMK Party is concerned, our Party General Secretary, Edappadi Palanisamy made it clear that in the AIADMK Party, there cannot be any dynastic politics. That was followed earlier by *Perarignar* Anna, *Puratchi Thalaivar* MGR, *Puratchi Thalaivi* Amma. We never followed dynastic politics. It is in a democratic way that our Party has been functioning. When I was the Law Minister, Dr. Gill was the Election Commissioner. I never interfered and he functioned independently. Now, Sir, you have appointed me as Chairman of the Committee on Government Assurances. For discussing reforms in the Election Commission, we asked representatives of the

Election Commission to appear before the Committee, but they said that they cannot appear before the Committee because they are an independent body and that we can ask only the Ministry to appear before the Committee. Therefore, the Election Commission still functions independently. The Government is not interfering. Hence, I don't think there is any necessity for his kind of a Bill.

MR. CHAIRMAN: Shri Deepak Prakash; two minutes.

श्री दीपक प्रकाश (झारखंड): सभापति महोदय, मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह विधेयक अमृतकाल में लाया गया है। यह गागर में सागर भरने वाला बिल है। यहां पर 2015 की रिट के बारे में कांग्रेस के कई सदस्यों ने चर्चा की है। वे आधे-अधूरे निर्णय को सदन के सामने ला रहे हैं, लेकिन यह सच है कि यह विधेयक अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्णय के अनुसरण में लाया गया। इस सदन को यह अधिकार है कि वह किसी भी कानून को बनाए या किसी भी कानून को निरस्त करे। हम सब लोगों को फ़ख्र है कि हम उस सदन के सदस्य हैं जहां पर कानून बनता है और कानून को निरस्त किया जाता है।

इस पूरे विधेयक में नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी है तथा इसमें लोकतांत्रिक ढंग से नियुक्ति की प्रक्रिया बनाई गई है। मैं इस विधेयक के अंतर्गत जानना चाहता हूं कि कांग्रेस के कालखंड में जब नियुक्ति की प्रक्रिया होती थी, तो क्या पहले सर्च कमेटी होती थी? क्या पहले कोई चयन समिति होती थी? पहले कांग्रेस के समय में न सर्च कमेटी होती थी, न चयन समिति होती थी, बल्कि 'खाता न बही, जो एक परिवार कहे, वही सही' होता था। मैं मेरे सामने बैठे हुए कांग्रेस के मित्रों और विपक्ष के मित्रों से ..(**समय की घंटी**).. 1989 में जब चुनाव आयोग में एक सदस्य होता था, तब एक ऑफिशियल ऑर्डर के माध्यम से उस वक्त के तत्कालीन प्रधान मंत्री ने दो लोगों को जोड़ दिया था। मैं पूछना चाहता हूं कि उस वक्त नियुक्ति की प्रक्रिया कहाँ चली गई थी? 1990 में जब वी.पी. सिंह की सरकार आई, तो उस वक्त ..(**व्यवधान**)..सर, मुझे एक मिनट का संरक्षण दे दीजिए। 1990 में जब वी.पी. सिंह की सरकार आई, तो फिर से एक आयुक्त की नियुक्ति हुई, लेकिन 1993 में, जब टी.एन. शेषन द्वारा चुनाव आयोग सुधार की प्रक्रिया तेज हुई, तो नरसिम्हा राव की सरकार ने एक और आयुक्त बनाकर...

MR. CHAIRMAN: Shri G.K. Vasan; you have two minutes.

SHRI G.K. VASAN (Tamil Nadu): Sir, as a modern democracy, the mammoth onus of conducting elections is on the Chief Election Commissioner. We have witnessed ballot boxes being carried through rough areas in this country. As a part of successive exercise of voting for crores of people in this country, my Party feels that, from time to time, it is necessary that we review the functioning of the electoral system, streamline the procedures and also provide adequate resources for the smooth conduct of elections. As a part of this exercise, successive Governments have brought

amendments to electoral laws like the Representation of the People's Act. Today, the law is being enacted with a lot of riders like Election Committee, Selection Committee, Search Committee or Qualification Committee to get the confidence of voters so that free and fair elections can take place in the country. I am sure that the hon. Minister will address the concerns of hon. Members. With this, I conclude. Thank you.

MR. CHAIRMAN: Very effective! The next speaker is Shri Ajay Pratap Singh. You have two minutes. श्री अजय प्रताप सिंह, आपके पास दो मिनट हैं।

श्री अजय प्रताप सिंह (मध्य प्रदेश): माननीय सभापति महोदय, सदन में जो बिल प्रस्तुत हुआ है, मैं उस बिल का समर्थन करता हूं। हमारे साथियों ने इस बिल के पक्ष और विपक्ष में अपने तर्क दिए हैं। हमारे विपक्षी साथियों ने बहुत अच्छा प्रवचन दिया है, लेकिन मैं उन्हें स्मरण कराना चाहता हूं कि इस देश में चुनाव में कदाचरण के कारण, अगर किसी का चुनाव निरस्त हुआ है, तो वह देश की पहली महिला प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी थीं, जिनके विरुद्ध इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था और जिसके परिणामस्वरूप देश को एक इमरजेंसी भोगनी पड़ी थी। दूसरा, मैं इन्हें यह भी स्मरण कराना चाहता हूं कि जब टी.एन. शेषन जी ने देशवासियों को चुनाव आयोग की ताकत का एहसास कराया था कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता क्या होती है, चुनाव आयोग की निर्भीकता क्या होती है, तब अगर किसी ने चुनाव आयोग के पाँव में बेड़ी डालने का काम किया है, तो वह तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है, इसलिए आज जब ये चुनाव आयोग की निष्पक्षता की बात करते हैं, तो इनकी बातें थोड़ी-सी बनावटी लगती हैं। हमारे साथियों ने इस बहस में भाग लेते हुए कहा है कि यहाँ पर चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, उनके अंतर्गत जो चयन समिति बनाई गई है, उसमें विपक्ष के नेता को रखा गया है और बहुमत सत्ता पक्ष का रखा गया है। ..(**समय की घंटी**)..जो वोट की बात करते हैं - अगर विपक्ष के नेता को रखा गया है, सत्ता पक्ष के लोगों को रखा गया है, तो आपस में डिस्कस करके एक अच्छे निर्णय पर पहुँचने के लिए कहा गया है। महोदय, हर समय, हर जगह वोट की बात नहीं होती है। इस डेमोक्रेसी का अर्थ है चर्चा करना, चर्चा के पश्चात निष्कर्ष निकालना और इस देश की बेहतरी के लिए कुछ काम करना। यह जो चयन समिति बनाई गई है, यह इसी उद्देश्य से बनाई गई है, इसलिए सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Shri Ramji - not present. Shrimati Priyanka Chaturvedi. You have two minutes. Make the most of it.

श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी (महाराष्ट्र): सर, मैं इतनी लंबी स्पीच बनाकर लाती हूँ, लेकिन टाइमिंग की वजह से लिट्रली सब कुछ बरबाद हो जाता है।

MR. CHAIRMAN: The world record for 100-metre race is 9 seconds. Go ahead.

श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी: सर, इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है, इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, इलेक्टोरल रोल्स अपडेट करना, जो एडल्ट्स हैं, जो वोट करते हैं, उन्हें इलेक्टोरल रोल्स में एनरोल करना ही नहीं होता है, बल्कि अगर पोलिटिकल पार्टीज़ में कोई डिस्प्यूट होता है या स्प्लिट अराइज़ होता है, तो ऐसे में निर्णायक डिसीजन और निष्पक्ष डिसीज़न लेने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की होती है। महाराष्ट्र में दो पार्टीज़ का स्प्लिट हुआ, जिनमें से एक का आर्ग्युमेंट अभी भी इलेक्शन कमीशन में चल रहा है और एक का सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सर, मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि अगर इलेक्शन कमीशन के डिसीज़ंस 2:1 होंगे, तो ये कहीं से निष्पक्ष नहीं होंगे। हर बार डिसीज़न में एक बायस्ड ही होगा। इसमें जो सेक्शन 8 इंट्रोड्यूस किया है, उसमें 'one versus none' हो गया है। अगर प्रधान मंत्री जी यह निर्णय ले लें कि यह जो सर्च कमिटी की च्वाइसेज़ हैं, सेलेक्ट कमिटी की च्वाइसेज़ हैं, उन्हें किसी का पालन नहीं करना है, उनका खुद का एक डिसीज़न होगा, as per Section 8 उसे भी मान्य रखा गया है। सर, मेरा मानना है और रिक्वेस्ट सिर्फ यह है, क्योंकि दो मिनट... सर, मेरे पास 50 सेकंड और हैं। सर, अगर सुप्रीम कोर्ट को क्वोट करूँगी, तो यहाँ पर दिक्कत होती है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने...

MR. CHAIRMAN: Thank you.

श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी: सर, अभी 40 सेकंड हैं। ...(**व्यवधान**)... जब कॉंस्टीट्यूशनल असेम्बली थी और कॉंस्टीट्यूशन बना था, तब बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने स्पिरिट में कहा था कि इसे गवर्नमेंट के इंटरफेयरेंस से दूर रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उसी स्पिरिट में अपना वर्डिक्ट दिया था। उसी स्पिरिट को बरकरार रखते हुए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि the Election Commission has to be totally fair and free of bias और यह मैं आपके माध्यम से, लॉ मिनिस्टर से कहना चाहती हूँ।

MR. CHAIRMAN: Shrimati Vandana Chavan. You have two minutes.

SHRIMATI VANDANA CHAVAN (Maharashtra): Sir, the Election Commission plays an exceptionally important role in upholding the democratic structure of our country. The test of credibility of the Election Commission is not only in their efficiency and the fairness of elections, but also in the neutrality where it has to show that it does not bow down to the ruling party. Lately, on the one hand, turning a blind eye by the Election Commission when the ruling party netas delivered hate speeches or resorted to indecent character assassination or quoting false facts and figures, and on the other side putting behind bars members of the opposition even at the slightest slip of

the tongue or which seemed like a slightest slip shows the changing role of the once extremely credible Election Commission.

In my limited time, I will just touch upon three points. First, I would like to ask the hon. Minister as to why the Government has not included the Chief Justice of India in the Selection Committee in spite of a specific directive in the Supreme Court ruling. Second, with so much executive control with the Election Commission, will it not become a 'yes man' of the present dispensation? Third, clause 6 says that the Search Committee is supposed to submit five Members on the panel. I want to ask: Why only five? Why not all the Members? That too, after submitting the five names, it is up to the Selection Committee whether they want to accept it or not, or just shun it totally.

With elections around the corner in 2024, with the sudden introduction of the Bill, that too bypassing the order of the Supreme Court, the move is suspect. This Bill, in the present form, in my submission, is a mockery of the expectations of the people and the democracy as a whole. Thank you, Sir.

SHRI DEREK O'BRIEN (West Bengal): Sir, I have a point of order.

MR. CHAIRMAN: Shri Arjun Ram Meghwal.

SHRI DEREK O'BRIEN: *

MR. CHAIRMAN: You were not here.

SHRI DEREK O'BRIEN: *

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, you were not present in the House. ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: *

MR. CHAIRMAN: No, it will not go on record. One second...*(Interruptions)*... Nothing will go on record. I have not given the floor. I had taken sense of the House.

* Not recorded.

The leaders had spoken to me. The House had authorized it, and even questioning the House ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: *

MR. CHAIRMAN: If you were not present, no one can help you. I am sorry. ...(*Interruptions*)... You are putting on record something which the House has approved. Sense of the House was taken. House is supreme. We cannot allow this. I have gone by the sense of the House.

Now, hon. Minister to reply to the discussion.

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY (West Bengal): Sir, I have a small clarification. ...(*Interruptions*)...

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): धन्यवाद सभापति महोदय ...(**व्यवधान**)... रिप्लाई के बाद क्लेरिफिकेशन हो जाएगी। आदरणीय सभापति महोदय, आज बिल पर जो चर्चा हुई, मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं, जिन्होंने चर्चा में भाग लिया। चर्चा कांग्रेस से श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने शुरू की और एनसीपी से श्रीमती वंदना चव्हाण जी ने समाप्त की। चर्चा में कुल 26 सदस्यों ने अपनी बात रखी। कुछ सदस्य जल्दी में बोले होंगे, लेकिन सुझाव बहुत शानदार थे, इसलिए मैं आपके माध्यम से सभी का आभार प्रकट करता हूं।

चेयरमैन सर, 1991 में एक एक्ट आया, जिसमें एक कमी रह गई थी। अदरवाइज़, यह हाउस में चर्चा में ही नहीं आता। अब 1991 में कैसे कमी रह गई, उस विषय में मैं नहीं जाऊंगा। आर्टिकल 324 में पार्लियामेंट एक्ट बनाए, यह संविधान निर्माताओं ने कहा था, लेकिन गलती रह गई कि 1991 तक नहीं बना। जो एक्ट 1991 में बनाया, उसका शीर्षक था - The Election Commission (Conditions of Service of Election Commissioners and Transaction of Business) Act, 1991. जब कोई पीआईएल में गया, तो उन्होंने कहा कि appointment के संबंध में तो आपने एक्ट ही नहीं बनाया। संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 324(2) में यह कहा था कि पार्लियामेंट के द्वारा इसकी appointment की प्रक्रिया को लेकर कानून बनाएंगे। इसलिए यह एक लिमिटेड परपज़ के लिए मैं आपके बीच आज खड़ा हूं। जब 1991 में इसमें कमी थी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून बनाओ। जब तक कानून नहीं बने, तब तक उन्होंने एक stop-gap arrangement किया, जिसका ये जिक्र कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी। ये बार-बार यही जिक्र कर रहे थे कि आप संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हो, संविधान में जो कहा गया है, उसको नहीं मानते हो। सर, चूंकि आप संविधान के ज्ञाता हैं, मैं कहता हूं कि आर्टिकल 324 भी संविधान निर्माताओं ने लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि संसद चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए

कानून बनाएगी। चेयरमैन सर, मैं आपका ध्यान चाहूंगा, आर्टिकल 50 भी संविधान निर्माताओं ने ही बनाया है, जिसका परपज़ है - separation of powers. ज्यूडिशियरी भी एक्जिक्यूटिव में इंटरफेयरेंस नहीं करेगी और एक्जिक्यूटिव भी ज्यूडिशियरी में इंटरफेयरेंस नहीं करेगी। यह separation of powers भी तो आर्टिकल 50 में है। हम उसके तहत यह बिल लेकर आए हैं।

श्री सभापतिः लेजिस्लेचर में भी इंटरफेयरेंस नहीं करेगी।

श्री अर्जुन राम मेघवालः जी सर, लेजिस्लेचर में भी इंटरफेयरेंस नहीं करेगी। सब अपना-अपना काम करेंगे। एक्जिक्यूटिव अपना काम करेंगे, लेजिस्लेटर अपना करेंगे और ज्यूडिशियरी अपना काम करेगी। यह जो आर्टिकल 50 है, यह संविधान निर्माताओं ने ही तो डाला है, तो संविधान से ऊपर कोई नहीं है। यह हम भी मानते हैं। हमें सुरजेवाला जी ज्ञान दे रहे थे, पता नहीं क्यों दे रहे थे। उन्होंने दो-तीन कहावतें भी कहीं। सर, एक कहावत मैं भी कहूंगा। सर, आप राजस्थानी हैं और मारवाड़ी भी जानते होंगे। वे बैठे भी होंगे। सुरजेवाला जी, शायद आपने हिये में कांछी नहीं फेरी। हिये का मतलब हृदय होता है। इसे कबीर की भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि आपने अंदर झांककर नहीं देखा और अगर अंग्रेजी में बोलूं - तो आप जो सारी कहावतें बोल रहे थे, वे ठीक नहीं थीं - Those who have not introspected themselves, वे हमें शिक्षा दे रहे हैं! आपने नवीन चावला साहब को कैसे बनाया, एम.एस. गिल साहब को कैसे बनाया, क्या आपको पता है? आइडियोलॉजी सबको पता थी, लेकिन हम उसमें जाना नहीं चाहते हैं। हम आज एक लिमिटेड परपज़ के लिए आपके बीच में हैं। मैं दो-चार जो मौलिक प्रश्न आए, जैसे अमर पटनायक साहब ने बहुत मौलिक प्रश्न उठाए ...(**व्यवधान**)...

SHRI RANDEEP SINGH SURJEWALA (Rajasthan): Sir, I have a point of order since the hon. Minister referred to me.

श्री अर्जुन राम मेघवालः हिय में कांची नहीं फेरी, मैंने इतना ही कहा था। मारवाड़ी में 'हिय' का मतलब है - 'हृदय' और 'कांची फेरने' का मतलब है कि अगर उसमें कोई गड़बड़ निकलती है, तो फुल इंट्रोस्पेक्शन करो, जैसे कबीर ने कहा कि अंदर झाँक कर देखो। इन्होंने अंदर झाँक कर देखा ही नहीं और हमारे ऊपर आरोप लगाने लगे। इन्होंने कहा कि संविधान से ऊपर कोई नहीं है। संविधान से ऊपर कोई नहीं है, हम भी मानते हैं। आप भी पढ़ लीजिए आर्टिकल 50, आप भी पढ़ लीजिए आर्टिकल 324. आपने 1991 में कानून में कमी क्यों रखी? मैं फिर बाबा साहेब को याद करते हुए कहूँगा, जो बाबा साहेब ने 25 नवंबर, 1949 को कहा था। इन्होंने भी क्वोट किया, मैं भी क्वोट करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, "हम इस बात का संकल्प करें कि जो बुराई हमारे मार्ग में है और जिनके कारण जनता के लिए सरकार को ..., उन बुराइयों को सुलझाने में विलंब नहीं करें।" सर, यह बुराई थी, क्योंकि इसमें कोई भी इंटरफेरेंस कर जाता था। अब यह तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, सबको पता है।

अच्छा, ये कह रहे हैं कि इसमें प्रधान मंत्री क्यों होना चाहिए! अब इस देश की जनता ने उन्हें चुना है। "WE, THE PEOPLE OF INDIA", यह हमारे संविधान का पहला वाक्य है। जनता

ने प्रधान मंत्री जी को चुना और सेलेक्शन कमेटी में प्रधान मंत्री नहीं होना चाहिए, मेरी समझ में नहीं आता कि ये कैसा आर्गुमेंट कर रहे थे! क्या एग्जीक्यूटिव फंक्शन में प्रधान मंत्री का कोई रोल ही नहीं है? जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, जिसे हमने इसमें सेलेक्शन कमिटी में दिया, उसका तो ज़िक्र ही नहीं किया, जिसने भी बोला!

सर, मैं आपके माध्यम से दो-तीन चीजें कहना चाहता हूँ। यह बिल एक लिमिटेड परपज़ के लिए है। 10 अगस्त, 2023 को मैंने राज्य सभा में यह बिल इंट्रोड्यूस किया था। हम 1991 के एक्ट को रिप्लेस करके यह बिल लेकर आए हैं। इसमें अपॉइंटमेंट का प्रावधान नहीं था, इसलिए हमने इसमें अपॉइंटमेंट का प्रावधान जोड़ा है। 2 मार्च, 2023 को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, उसमें यही कहा गया था। उन्होंने कहा कि जब तक संसद कोई कानून नहीं बनाती, तब तक हम यह कमिटी बनाते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के कहने के अनुसार ही हम बिल लेकर आए हैं।

सर, अमर पटनायक साहब ने रिमूवल के बारे में कहा। रिमूवल के प्रावधान के बारे में जहाँ तक मैं समझता हूँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसी तरीके और उसी ग्राउंड के आधार पर हटाया जा सकता है, जिस प्रक्रिया से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 124 के क्लॉज़ 4 में उस प्रक्रिया का वर्णन है, जिसके तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए जिस प्रक्रिया का वर्णन दिया हुआ है, वही प्रक्रिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए होगी। जहाँ तक इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की बात है, उसके लिए भी संविधान में लिखा हुआ है। आर्टिकल 324 में लिखा हुआ है। जहाँ तक इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की बात है, इसके विषय में संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत क्लॉज़ 5 के तहत प्रावधान है कि इलेक्शन कमिश्नर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अनुशंसा पर हटाया जा सकता है। ये दोनों चीजें क्लियर हैं। आपने यह मुद्दा उठाया था, इसलिए मैंने इसका ज़िक्र किया।

दूसरा, किसी ने कहा कि जो चुनाव नहीं कराते हैं, वे चुनाव को क्या जानते हैं। मैं भी जिले में जिला कलेक्टर रहा। उस समय तो हमने कोई चुनाव लड़ा ही नहीं, तो क्या हम चुनाव नहीं कराते थे? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग की जो कार्य प्रणाली है, वह निष्पक्ष है, निष्पक्ष रहेगी और सरकार भी उसे निष्पक्ष रखने के लिए प्रतिबद्ध है। नरेन्द्र मोदी जी के कालखंड में जितनी भी संस्थाएँ हैं, वे निष्पक्ष तरीके से काम करें, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। ...(**व्यवधान**)... है ही साहब, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अभी मैंने एम.एस. गिल साहब का नाम लिया, चावला साहब का नाम लिया। अच्छा, अभी किसी ने ज़िक्र किया था, ठाकुर साहब ने कहा या पता नहीं किसने कहा कि अभी जयप्रकाश नारायण होते, तो हमारा विरोध करते। सर, मैं स्पष्ट कहता हूँ कि अगर जयप्रकाश नारायण जिंदा होते, तो वे नरेन्द्र मोदी जी का समर्थन करते। वे 100 परसेंट नरेन्द्र मोदी जी का समर्थन करते, इसमें कोई शक नहीं है। ...(**व्यवधान**)... अच्छा मनोज झा साहब ने कहा था। वे नरेन्द्र मोदी जी का ही समर्थन करते।

सर, मैं एक ऑफिशियल अमेंडमेंट भी लेकर आया हूँ। जब यह मूल बिल आया था, उसमें चर्चा में काफी चीजें आई थीं। सरकार संवेदनशील है, इसलिए सोचती है।

श्री सभापतिः माननीय मंत्री जी, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने कुछ महत्वपूर्ण संकेत दिए थे, आप उन पर तो सहमति व्यक्त कर सकते हैं। इन्होंने खास तौर से four fundamentals of Election Commission कहा था।

श्री अर्जुन राम मेघवालः हाँ, मैं सहमति प्रकट करता हूँ। "निष्पक्षता, निर्भीकता, पारदर्शिता", मुझे याद भी है, सर।

श्री सभापतिः शुचिता।

श्री अर्जुन राम मेघवालः शुचिता।

श्री सभापतिः फिर इन्होंने यह अनुरोध किया था कि इनका संरक्षण कीजिए।

श्री अर्जुन राम मेघवालः सर, इन्होंने हिय में कांची नहीं फेरी। विषय एक ही था। सर, मैं जो official amendment लेकर आया हूँ, इसमें एक क्लॉज़ 6 जो था, उसमें सर्च कमेटी का विषय था, उसे हमने थोड़ा चेंज किया है। पहले वह कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में थी, अब वह लॉ मिनिस्ट्री की अध्यक्षता में है और दो सेक्रेटरीज़ उसके मेम्बर हैं।

महोदय, कई सदस्यों ने सैलरी का विषय रखा, तिरूची शिवा साहब ने भी सैलरी का विषय रखा, लेकिन official amendment के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर सैलरी का प्रावधान कर दिया गया है। Condition of Service - क्लॉज़ 15 में हमने एक official amendment किया है, जिसमें राष्ट्रपति जी रूल्स को नोटिफाई करके निर्धारित करेंगे और अधिसूचित करेंगे, यह प्रावधान हमने कर दिया है। हमने एक क्लॉज़ 15ए जोड़ा है, जो महत्वपूर्ण है। चूँकि महबूब नगर में, तेलंगाना में एक विषय आया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमिश्नर को किसी ट्रायल जज ने नोटिस भिजवा दिया था, तो प्रोटेक्शन से सम्बन्धित एक क्लॉज़ हमने 15ए जोड़ा है। CEC या EC अपनी ड्यूटी करते समय कोई कार्रवाई सम्पादित करेंगे, ड्यूटी करते समय कोई सुनवाई या कोई भी आदेश देंगे, तो ऐसे प्रकरणों में उन पर कोई कोर्ट कार्रवाई नहीं कर सकेगा, यह प्रोटेक्शन की बात हमने कही है।

महोदय, मैं दो-तीन और चीज़ें कह कर अपनी बात को समाप्त करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आप भी 6 बजे तक वोटिंग का कह रहे थे। आपने एक बात यह कही कि IAS ही क्यों? शायद माननीय सुरजेवाला जी ने कहा था। 1951 और 1952 से लेकर अब तक तो चुनाव हो ही रहे हैं। देश में चुनाव आयोग की साख भी बढ़ी है, तो अब तक तो ऐसी कोई गड़बड़ नहीं हुई है। हमारे चड्ढा साहब अभी शायद बैठे हैं। ये कह रहे हैं कि आप तो किसी को भी बना सकते हैं। साहब, आप बिल तो पूरा पढ़ लीजिए। उसमें क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। इसमें जो क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, उस क्वालिफिकेशन के अनुसार ही कोई बनेगा, किसी अन्य को हम नहीं बना सकते। सेक्रेटरी रैंक - यह क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। आपको तो इस बिल को पढ़ ही लेना चाहिए था।

...(**व्यवधान**)...

सर, जवाहर सरकार साहब ने कुछ मुद्दे उठाए। आपने अच्छी बात कही है कि कहीं बाढ़ आ गयी थी, तो बोट पर भी चुनाव की प्रक्रिया - यह अच्छी बात है। बोट पर भी चुनाव की प्रक्रिया की बात कही। मैं तो राजस्थान का, रेगिस्तान का रहने वाला हूँ। मेरे यहाँ तो धोरे हैं, sand dunes हैं। मैंने देखा कि लोग ऊँट पर वोट देने जाते थे। चुनाव आयोग की इतनी खासियत है कि हमारा जो दूर का गाँव था, उसके लिए ऊँट रखते थे कि ऊँट पर बैठ कर वोट देने जाओ। तो चुनाव आयोग द्वारा ये सारी प्रक्रियाएँ होती रही हैं। ऐसे हम year to year, election to election सीखते आये हैं। चुनाव आयोग ने अपनी साख भी कमायी है और निष्पक्षता भी बरकरार रखी है।

सर, एक विषय जो शायद चड्ढा साहब ने कहा था, मुझे पता नहीं कांग्रेस पार्टी उसे कैसे लेगी। इन्होंने कहा कि आप कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स कर लो, मेरे सुझाव मान लो, मैं सारे अपोजिशन को एक कर दूँगा। क्या ये खरगे साहब का रूप धारण करके बोल रहे थे, यह मेरी समझ में नहीं आया!

MR. CHAIRMAN: Ignore it.

श्री अर्जुन राम मेघवाल: मुझे थोड़ा सा confusion हो गया था। मैंने कहा कि क्या विषय था ...(**व्यवधान**)...

SHRI RANDEEP SINGH SURJEWALA: Sir, I have a point of order. ...(*Interruptions*)... Sir, I have a right to...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Randeep Singh Surjewala *ji*, there is no reflection on you. ...(*Interruptions*)... It was not attributed to you. ...(*Interruptions*)... No, No. ...(*Interruptions*)... I have taken note of it. ...(*Interruptions*)... It was attributed neither to you nor to Shri Raghav Chadha.

श्री अर्जुन राम मेघवाल: आपने कहा था। वह मैंने सुना है। ...(**व्यवधान**)... आपने कहा था कि आप मेरे सुझाव मान लें, मैं सारे अपोजिशन को एक कर दूँगा। आप लीडर ऑफ दि अपोजिशन की तरह बोल रहे थे, तो मैंने इतना ही कहा कि क्या आपने खरगे साहब का स्थान ले लिया।

MR. CHAIRMAN: This is a lighter moment. Go ahead.

श्री अर्जुन राम मेघवाल: सर, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि हम यह जो बिल लेकर आये हैं, यह सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले के खिलाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिये हैं, उनके तहत ही हम इसे लेकर आये हैं; संविधान के आर्टिकल 324(2) में जो प्रावधान हैं, उनके तहत ही हम इसे लेकर आये हैं; आर्टिकल 50 में जो separation of powers है, जो संविधान में लिखा हुआ है, उसके तहत ही हम इसे लेकर आये हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करूँगा कि इस बिल को सर्वसम्मति से पास करें, यह बहुत progressive law है। थैंक यू, सर।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: माननीय सभापति जी, ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: There is no provision for clarification. I shall now put... ...(*Interruptions*)... Nothing will go on record. ...(*Interruptions*)... Okay. ...(*Interruptions*)... Mr. Sukhendu Sekhar Ray. ...(*Interruptions*)... He had indicated earlier also.

SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY: Sir, I have only one constitutional point because according to my Party, this Bill suffers from unreasonableness and arbitrariness. Why I am saying so? It is because there is no reasonable nexus between the objects and the provisions of the Bill in as much as nothing is spelt out in the Bill as to why the Chief Justice has been replaced by a Minister although the norm set up by the Supreme Court continued for eight long years and continues to hold good. So, why is this replacement? There is no clarification from the Minister.

MR. CHAIRMAN: Okay. ...(*Interruptions*)... I shall now put the amendment moved by Dr. John Brittas for reference of the Chief Election Commissioner and other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Bill, 2023, to a Select Committee of the Rajya Sabha to vote.

The question was put and the motion was negatived.
...(Interruptions)...

(At this stage, some hon. Members left the Chamber.)

SHRI ELAMARAM KAREEM (Kerala): Sir, you did not call me personally. ...(*Interruptions*)... You are only reading. ...(*Interruptions*)... I moved the amendment. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: No, no. You are part of a committee. ...(*Interruptions*)...

SHRI ELAMARAM KAREEM: Each and every Member should be called and asked whether he is moving it or not. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Take your seat. ...(*Interruptions*)... Please take your seat. Hon. Members, I am scrupulously following the procedure. It was already indicated

whether you wanted to move. That has been moved. Now, it is negatived. The amendment is negatived. ...(*Interruptions*)...

I shall now put the amendment moved by Dr. V. Sivadasan for reference of the Chief Election Commissioner and other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Bill, 2023, to a Select Committee of the Rajya Sabha to vote.

The question was put and the motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: Now, the question is:

That the Bill to regulate the appointment, conditions of service and term of office of the Chief Election Commissioner and other Election Commissioners, the procedure for transaction of business by the Election Commission and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 5, there are three Amendments; Amendments (Nos. 1 and 2) by Dr. John Brittas and Amendment (No. 17) by Shri Elamaram Kareem. Dr. John Brittas, are you moving the Amendments? Yes or no.

Clause 5 - Qualifications of Chief Election Commissioner and other Election Commissioners

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, I move:

(No. 1) That at page 2, line 20, ***for*** the words "are holding or have held", the words "have been a Judge of the Supreme Court or Chief Justice of a High Court or have held" be ***substituted***.

(No. 2) That at page 2, ***after*** line 22, the following proviso be ***inserted***, namely,—

" Provided that such persons should have completed at

least one year after their retirement without accepting any post-retirement employment in the Central Government or any of the State Governments, immediately preceding the date of consideration of their name for appointment either as Chief Election Commissioner or Election Commissioner."

MR. CHAIRMAN: Now, Amendment (No.17) by Shri Elamaram Kareem. Is he here? *...(Interruptions)...*

SHRI ELAMARAM KAREEM: Sir, I move:

(No. 17) That at page 2, line 20, the words "are holding or", be ***deleted***

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendments (Nos. 1 and 2) moved by Dr. John Brittas to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendment (No.17) moved by Shri Elamaram Kareem to vote.

The motion was negatived.

Clause 5 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 6, there are four Amendments; Amendment (No. 3) by Dr. John Brittas, Amendment (No. 18) by Shri Elamaram Kareem, Amendment (No. 24) by Shri K.C. Venugopal, not present, and Amendment (No. 33) by Shri Arjun Ram Meghwal. Are you moving the Amendments? Amendments moved except Shri K.C. Venugopal who is not present and Shri Elamaram Kareem, not present. Dr. John Brittas, are you moving?

Clause 6 - Search Committee

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, I move:

(No. 3) That at page 2, line 23, ***for*** the words "Cabinet Secretary", the words "incumbent Chief Election Commissioner", be ***substituted***.

MR. CHAIRMAN: Shri Elamaram Kareem, not present. Shri K.C. Venugopal, not present. Shri Arjun Ram Meghwal, are you moving?

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: Sir, I move:

(No. 33) That at page 2, ***for*** lines 23 to 25, the following be ***substituted***, namely:-

"6. A Search Committee headed by the Minister of Law and Justice and comprising of two other members not below the rank of Secretary to the Government of India, shall prepare a panel of five persons for".

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendment (No.3) moved by Dr. John Brittas to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendment (No.33) moved by Shri Arjun Ram Meghwal to vote. The question is:

(No. 33) That at page 2, ***for*** lines 23 to 25, the following be ***substituted***, namely:-

"6. A Search Committee headed by the Minister of Law and Justice and comprising of two other members not below the rank of Secretary to the Government of India, shall prepare a panel of five persons for".

The motion was adopted.

Clause 6, as amended, was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 7, there are eight Amendments; Amendments (No. 4 and 5) by Dr. John Brittas, Amendments (No. 19 and 20) by Shri Elamaram Kareem, not present, Amendment (No. 25) by Shri K.C. Venugopal, not present and Amendments (Nos. 26 and 27) by Dr. V. Sivadasan, not present. *...(Interruptions)...*

DR. V. SIVADASAN: Sir, I am present.

MR. CHAIRMAN: Good, I have noted your presence. You are very elegantly dressed today. *...(Interruptions)...* Amendment (No. 30) by Prof. Manoj Kumar Jha, not present. Dr. Brittas, are you moving?

Clause 7 - Selection Committee

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, I move:

(No. 4) That at page 2, line 33, ***for*** the words "a Union Cabinet Minister to be nominated by the Prime Minister", the words "the Chief Justice of India or a Judge of the Supreme Court to be nominated by him", be ***substituted***.

(No. 5) That at page 2, lines 38 to 40, be ***deleted***.

MR. CHAIRMAN: Now, Amendments (Nos. 26 and 27) by Dr. V. Sivadasn.

DR. V. SIVADASAN (Kerala): Sir, I move:

(No. 26) That at page 2, line 33, ***for*** the words "a Union Cabinet Minister to be nominated by the Prime Minister", the words "a Judge of the Supreme Court of India nominated by the Chief Justice of India", be ***substituted***.

(No. 27) That at page 2, lines 38 to 40, be ***deleted***.

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendments (No.4 and 5) moved by Dr. John Brittas to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendment (No.26 and 27) moved by Dr. V. Sivadasan to vote.

The motion was negatived.

Clause 7 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 8, there are two Amendments; Amendment (No. 6) by Dr. John Brittas and Amendment (No. 31) by Prof. Manoj Kumar Jha. Are you moving the Amendments?

6.00 **P.M.**

Dr. John Brittas, are you moving the Amendment? No; your voice is loud enough.

DR. JOHN BRITTAS: Sir, at least, I need to say in mic.

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, now it is 6.00 p.m. If the House agrees, we may extend the sitting beyond 6.00 p.m. for disposal of the Bill.

Clause 8 --Powers of Selection Committee to regulate its own procedure

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, I move:

(No.6) That at page 3, lines 3 and 4, be ***deleted***.

The question was put and the motion was negatived.

Clause 8 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 9, there are five Amendments; Amendments (Nos. 7 and 8) by Dr. John Brittas; Amendment (No.21) by Shri Elamaram Kareem; not present; Amendment (No.28) by Dr. V. Sivadasan and Amendment (No.32) by Prof. Manoj Kumar Jha; not present. Dr. John Brittas, are you moving your Amendments?

Clause 9 --Term of Office

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, I move:

(No.7) That at page 3, line 7 ***for*** the words, "sixty-five", the word "seventy", be ***substituted***.

(No.8) That at page 3, ***after*** line 12, the following be ***inserted***, namely:-

"*(4)* The Chief Election Commissioner and other Election Commissioners shall not, for a period of one year from the date on which they cease to hold office as such, accept any employment either under the Central Government or under any State Government.".

MR. CHAIRMAN: Dr. Sivadasan, are you moving your Amendment?

DR. V. SIVADASAN (Kerala): Sir, I move:

(No.28) That at page 3, ***for*** lines 8 and 9, the following be ***substituted***, namely:-

"The Chief Election Commissioner shall not be eligible for re-appointment or for any other postings under the Central Government or any of the State

Governments, whereas other Election Commissioners shall not be eligible for re-appointment."

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendments (No. 7 and 8) moved by Dr. John Brittas to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendment (No. 28) moved by Dr. V. Sivadasan to vote.

The motion was negatived.

Clause 9 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 10, there are eight Amendments; Amendments (Nos. 9 to 13) by Dr. John Brittas and Amendments (Nos. 34 to 36) by Shri Arjun Ram Meghwal. Dr. John Brittas, are you moving your Amendments?

Clause 10 --Salary, etc.

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, I move:

(No.9) That at page 3, lines 17 and 18, ***for*** the words "the Cabinet Secretary", the words "a Judge of the Supreme Court", be ***substituted***.

(No.10) That at page 3, ***after*** line 21, the following be ***inserted***, namely:-

"Provided further that conditions of service of the Chief Election Commissioner and other Election Commissioners shall not be varied to their disadvantage after appointment.".

(No.11) That at page 3, line 33, ***for*** the words "Cabinet Secretary", the words "a Judge of the Supreme Court", be ***substituted***.

(No.12) That at page 3, line 39, ***after*** the word, "such, "the words, "subject to the provisions of section 5, ", be ***inserted***.

(No.13) That at page 3, line 40, ***for*** the words "Cabinet Secretary", the words "a Judge of the Supreme Court", be ***substituted***.

MR. CHAIRMAN: Now, hon. Minister.

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: Sir, I move:

(No.34) That at page 3, ***for*** lines 16 to 18, the following be ***substituted***, namely:-

"10. *(1)* The Chief Election Commissioner and other Election Commissioners shall be paid a salary which is equal to the salary of a Judge of the Supreme Court:".

(No.35) That at page 3, line 33, ***for*** the words "Cabinet Secretary", the words "Judge of the Supreme Court" be ***substituted***.

(No.36) That at page 3, line 40, ***for*** the words "to the Cabinet Secretary", the words "in accordance with the rules for the time being applicable to the service to which he belonged before his appointment as Chief Election Commissioner or an Election Commissioner" be ***substituted***.

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendments (Nos. 9 to 13) moved by Dr. John Brittas to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendments (Nos. 34 to 36) moved by the hon. Minister to vote. The question is:

(No.34) That at page 3, ***for*** lines 16 to 18, the following be ***substituted***, namely:-

"10. *(1)* The Chief Election Commissioner and other Election Commissioners shall be paid a salary which is equal to the salary of a Judge of the Supreme Court:".

(No.35) That at page 3, line 33, ***for*** the words "Cabinet Secretary", the words "Judge of the Supreme Court" be ***substituted***.

(No.36) That at page 3, line 40, ***for*** the words "to the Cabinet Secretary", the words "in accordance with the rules for the time being applicable to the service to which he belonged before his appointment as Chief Election Commissioner or an Election Commissioner" be ***substituted***.

The motion was adopted.

Clause 10, as amended, was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 11, there are two Amendments; Amendment (No. 14) by Dr. John Brittas and Amendment (No.37) by Shri Arjun Ram Meghwal. Dr. John Brittas, are you moving your Amendment?

Clause 11 --Resignation and Removal

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, I move:

(No.14) That at page 3, ***for*** lines 44 and 45, the following be ***substituted***, namely:-

"removed from office except in accordance with the manner and grounds for removal of a Judge of the Supreme Court, as laid down in clauses (4) and (5) of article 124. ".

MR. CHAIRMAN: Now, hon. Minister.

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: Sir, I move:

(No.37) That at page 2, ***for*** lines 43 to 45, the following be ***substituted***, namely:-

"*(2)* The Chief Election Commissioner shall not be removed from his office except in like manner and on the like grounds as a Judge of the Supreme Court.

(3) The other Election Commissioner shall not be removed from office except on the recommendation of the Chief Election Commissioner. ".

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendment (No. 14) moved by Dr. John Brittas to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendment (No.37) moved by hon. Minister to vote. The question is:

(No.37) That at page 2, ***for*** lines 43 to 45, the following be ***substituted***, namely:-

"*(2)* The Chief Election Commissioner shall not be removed from his office except in like manner and on the like grounds as a Judge of the Supreme Court.

(3) The other Election Commissioner shall not be removed from office except on the recommendation of the Chief Election Commissioner. ".

The motion was adopted.

Clause 11, as amended, was added to the Bill.

Clause 12 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 13, there is one Amendment; Amendment (No. 15) by Dr. John Brittas.

Clause 13 --Pension

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, I move:

(No.15) That at page 4, lines 9 to 18, be ***deleted***.

The question was put and the motion was negatived.

Clause 13 was added to the Bill.

Clause 14 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 15, there is one Amendment--in the long race, at last, Dr. John Brittas has made an exit--Amendment (No.38) by Shri Arjun Ram Meghwal. ...*(Interruptions)*....

DR. JOHN BRITTAS: Sir, I am there. My amendment is to protect the Election Commission. ...*(Interruptions)*....

MR. CHAIRMAN: Your amendment is not there. ...*(Interruptions)*.... Now, the Minister.

Clause 15- Other conditions of Service

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: Sir, I move:

(No.38) That at page 4, ***for*** lines 28 to 31, the following be ***substituted***, namely:-

"15. Save as otherwise provided in this Act, the President may by rules determine the conditions of service relating to travelling allowance, medical facilities, leave travel concession, conveyance facilities, and such other conditions of service relating to the Chief Election Commissioner and other Election Commissioners."

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendment (No.38) moved by hon. Minister to vote. The question is:

(No.38) That at page 4, ***for*** lines 28 to 31, the following be ***substituted***, namely:-

"15. Save as otherwise provided in this Act, the President may by rules determine the conditions of service relating to travelling allowance, medical facilities, leave travel concession, conveyance facilities, and such other conditions of service relating to the Chief Election Commissioner and other Election Commissioners."

The motion was adopted.

Clause 15, as amended, was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: There is one Amendment (No.39) by Shri Arjun Ram Meghwal for insertion of new Clause 15A.

New Clause 15A-Protection of Chief Election Commissioner and other Election Commissioners

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: Sir, I move:

(No. 39) That at page 4, ***after*** line 31, the following be ***inserted***, namely:-

"15A. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no court shall entertain or continue any civil or criminal proceedings against any person who is or was a Chief Election Commissioner or an Election Commissioner for any act, thing or word, committed, done or spoken by him when, or in the course of acting or purporting to act in the discharge of his official duty or function."

MR. CHAIRMAN: I shall now put Amendment (No.39) moved by hon. Minister to vote. The question is:

(No. 39) That at page 4, ***after*** line 31, the following be ***inserted***, namely:-

"15A. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no court shall entertain or continue any civil or criminal proceedings against any person who is or was a Chief Election Commissioner or an Election Commissioner for any act, thing or word, committed, done or spoken by him when, or in the course of acting or purporting to act in the discharge of his official duty or function."

The motion was adopted.

Clause 15A was added to the Bill.

Clause 16 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 17, there are two Amendments; Amendment (No.16) by Dr. John Brittas and Amendment (No. 29) by Dr. V. Sivadasan. Dr. Brittas, are you moving your Amendment?

Clause 17- Disposal of Business

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, I move:

(No.16) That at page 4, line 39, ***for*** the words, "All business", the words "Save as provided in sub-section *(1)*, all business", be ***substituted***.

MR. CHAIRMAN: Dr. V. Sivadasan, are you moving the Amendment?

DR. V. SIVADASAN: Sir, I move:

(No.29) That at page 4, line 38, after the words "other Election Commissioners", the words, "and as far as possible, written rules shall be laid down for the conduct of the business of the election Commission", be ***inserted***.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendment (No.16) moved by Dr. John Brittas to vote.

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Amendment (No.29) moved by Dr. V. Sivadasan to vote.

The motion was negatived.

Clause 17 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 18, there is one Amendment (No. 22) by Shri Elamaram Kareem; not present.

Clause 18 was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: In Clause 19, there are five Amendments; Amendment (No.23) by Shri Elamaram Kareem and Amendments (Nos. 40 to 43) by Shri Arjun Ram Meghwal. Shri Elamaram Kareem; not present. Now, the Minister.

Clause 19-Laying

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: Sir, I move:

(No.40) That at page 5, line 8, ***for*** the words "order made under section 18", the words "rule and order made under this Act" be ***substituted.***

(No.41) That at page 5, line 12, ***for*** the word "order", the words "rule or order" be ***substituted.***

(No.42) That at page 5, line 13, ***for*** the word "order", wherever it occurs, the words "rule or order" be ***substituted.***

(No.43) That at page 5, line 16, ***for*** the word "order", the words "rule or order" be ***substituted.***

MR. CHAIRMAN: I shall now put AmendmentS (No. 40 to 43) moved by hon. Minister to vote. The question is:

(No.40) That at page 5, line 8, ***for*** the words "order made under section 18", the words "rule and order made under this Act" be ***substituted.***

(No.41) That at page 5, line 12, ***for*** the word "order", the words "rule or order" be ***substituted.***

(No.42) That at page 5, line 13, ***for*** the word "order", wherever it occurs, the words "rule or order" be ***substituted.***

(No.43) That at page 5, line 16, ***for*** the word "order", the words "rule or order" be ***substituted.***

The motion was adopted.

Clause 19, as amended, was added to the Bill.

Clause 20 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Arjun Ram Meghwal to move that the Bill, as amended, be passed.

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: Sir, I move:

That the Bill, as amended, be passed.

The question was put and the motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet at 11.00 A.M. on Tuesday, the 13th December, 2023.

The House then adjourned at twelve minutes past six of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 13th December, 2023.